www.ghoonghatkibagawat.com ghoonghatkibagawat37@gmail.com ghoonghatkibagawat.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र)

वर्ष : 23 | अंक : 33 | गोरखपुर | 25 फरवरी 2024 | पृष्ठ : 08 | मूल्य: 2/–

बजटीय आवंटन को आठ मार्च तक लौटाएं

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों से वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खर्च न किए गए बजटीय आवंटन को आठ मार्च तक वापस करने को कहा है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान में हुई प्रत्याशित बचत को स्वीकार करने की अंतिम तिथि आठ मार्च, 2024 तय की गई है। ज्ञापन के मुताबिक, मंत्रालयों एवं विभागों से कहा गया है कि विनियोग के हरेक खंड के तहत बचत राशि के समर्पण का विवरण एक निर्दिष्ट प्रारूप में उक्त तिथि तक वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग को भेजा जा सकता है।

इसके मुताबिक, मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे बचत जमा करने की सूचना देते समय मूल अनुमान या वसूली के मुकाबले संबंधित अनुदान में वसूली में अधिकता या कमी, प्राप्तियों, यदि कोई हो, का विवरण भी दें।

तीन आपराधिक अधिनियम एक जुलाई से

❑हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान के अमल पर रोक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ एक जुलाई 2024 से अमल में आ जाएगा लेकिन हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान के अमल पर रोक रहेगी। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बनाए गए तीनों नए कानून को एक जुलाई 2024 से अमल में लाने के लिए नोटिफाई कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को एक जुलाई से लागू किया जाएगा लेकिन नो. टिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा–106 (2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है यानी धारा–106 (2) फिलहाल लागू नहीं होगा यह प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अप. राध से जुड़ा हुआ है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद अमल में लाया जाएगा।

केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की ओर से इस मामले में शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि तीनों क्रिमिनल लॉ एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सिर्फ धारा–106 (2) अभी अमल में नई आएगा। संसद से तीनों कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को पास हो गया था जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर 25 दिसंबर 2023 को मुहर लगा दी थी। पुराने औपनिवेशिक काल के कई शब्दावली को हटा दिया गया है। ऐसे करीब 475 शब्दों को डिलीट किया गया है जिनमें लंदन गजट, ज्यूरी, हर हैनिस आदि शामिल हैं। पहले जहां चार सौ बीस (420) यानी धोखाधड़ी, दफा 302 यानी हत्या व 376 यानी रेप जैसे अपराध के लिए कानून की किताब में लिखी धाराएं लोगों के जुबान पर चढ़ी हुई थी वह सब अब बदल गई है।

कुल 358 धाराएं और 20 नए अपराध

भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और उसमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। जिनमें स्नेचिंग से लेकर मॉब लिंचिंग शामिल किया गया है। साथ ही 33 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है। साथ ही 83 ऐसी धाराएं या अपराध हैं जिनमें जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। ?ऐसे 23 अपराध हैं जिनमें न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था जिसें न्यूनतम सजा को शुरू किया गया है। 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक व समुदायिक सेवा को भी रखा गया है। पहले यह नहीं था। राजद्रोह जैसे अपराध को अब नए कानून में हटा दिया गया। बीएन 2 संहिता की धारा–113 में आतंकवाद से संबंधित परिभाषा और सजा का प्रिावधान है।

युवाओं के लिए अवसरों की अब कोई कमी नहीं : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि युवाओं के लिए अवसरों की अब कोई कमी नहीं है। आज युवाओं पर अपना और राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दायित्व है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि नीति निर्धारण और प्रौद्योगिकी विकास में परिवर्तन युवाओं को एक समान अवसर प्रदान कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने स्नातक युवाओं को अपने भविष्य के सपनों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भारत की परंपरा के अनुरूप युवाओं को समूचे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहिए। डपराष्ट्रपति ने स्नातक युवाओं को गैर परंपरागत करियर की राह अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रतिस्पर्धि परीक्षाओं तक खुद को सीमित नहीं करना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत बनाने की कुंजी युवाओं के हाथों में है।

आसान नहीं एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाना

किसान नेता अपने आंदोलन को अराजनीतिक बताते हैं। लेकिन राजनीतिक संगठनों के साथ उनके रिश्ते जगजाहिर हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन तो बहाना है–असली काम तो मोदी सरकार को हटाना है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान के तहत देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है। लेकिन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून की गारंटी के लिए आंदा. लनरत किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें मंगवाने के पक्षधर नहीं दिखते। सरकार बातचीत के माध्यम से समस्या सुलझाना चाहती है। लेकिन किसान नेताओं के तेवरों और मांगों की लंबी सूची के दृष्टिगत इस बात की संभावना न्यून है कि बातचीत से ये मसला निपटेगा। वास्तव में किसान नेता भी जानते हैं कि एमएसपी कानून की गारंटी देना इस सरकार तो क्या किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है।

किसानों के असली इरादों को उनकी तैयारियों को दे खकर समझा जा सकता है। जिस तरह ट्रैक्टर ट्रालियों में महीनों का राशन और दूसरा जरूरी सामान लेकर वो घरों से निकले हैं, उससे साफ है कि उनकी मंशा समझौते की नहीं, टकराव की है। वो चाहते हैं कि गलती से शासन प्रशासन के हाथों कोई ऐसा काम हो जाए, जिससे वो और उनका पूरा इको सिस्टम सरकार को किसान विरोधी साबित कर सके। ये सारी कवायद चुनाव से पहले माहौल खराब करने और सरकार की छवि को ठेस पहुंचाने की दिखाई देती है।

किसान समस्या का हल चाहते तो बातचीत में विश्वास करते। वो तो दिल्ली की तरफ हजारों की भीड़ लेकर ट्रैक्टर ट्रालियों, गाड़ियों और अन्य साधनों से दिल्ली की ओर ऐसे बढ़े मानो उन्हें किसी विदेशी सरकार से निर्णायक संघर्ष करना है। किसान नेता जब मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच से बोलते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो केंद्र सरकार उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मीडिया से बातचीत के समय किसान नेताओं और उनके समर्थकों की भाषा, बॉडी लैग्वेंज और भाषणों की टोन ऐसी होती हैं मानो किसी दुश्मन देश की सरकार को वो चेतावनी दे रहे हों। करोड़ों नागरिकों द्व ारा निर्वाचित सरकार, जो बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, उसके प्रति किसान नेताओं का अनादर का भाव कदम कदम पर दिखाई देता है। किसान नेता अपने आंदोलन को अराजनीतिक बताते हैं। लेकिन राजनीतिक संगठनों के साथ उनके रिश्ते जगजाहिर हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन तो बहाना है–असली काम तो मोदी सरकार को हटाना है। लोगों में चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर बिना राजनीतिक दलों के समर्थन के इतना बड़ा आंदोलन इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो सकता है। 2020 में तीन कृ षि कानूनों को लेकर पंजाब के 34 किसान संगठन विरोध कर रहे थे, जबकि यह आंदोलन मात्र कुछ किसान संगठनों द्वारा ही किया जा रहा है। तो क्या यह सही है कि इस बार का आंदोलन किसी विशेष उद्देश्य से हो रहा है?

भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल इस बार किसान आंदोलन के सबसे प्रमु ख चेहरे हैं। जिस तरह पिछली बार गुरुनाम सिंह चढूनी और राकेश टिकैत थे इस बार डल्लेवाल हैं। उनके मुंह से किसान आंदोलन की सच्चाई निकल गई है। डल्लेवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसे नीचे लाना है। आंदोलन में शामिल पंजाब के किसान नेता तेजवीर सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो किसान आंदोलन के जरिए देश की सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं वो किसान आंदोलन को विपक्ष की लड़ाई लड़ने वाला भी बता रहे हैं। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं किसान नेताओं को एक बात समझाई गई है कि ये लड़ाई किसानों के अधिकारों और एमएसपी की गारंटी के लिए नहीं है बल्कि इन मुद्दों के नाम पर सरकार को ही बदलना है।

यही नहीं किसान आंदोलन को कवर कर रहे बहुत से यूट्यूबरों, मीडिया हाउसेस के वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर आप यही कह सकते हैं कि किसान आंदोलन भ्रमित है या गलत लोगों के हाथ में है। बहुत से किसान इंडिपेंडेंट पंजाब या खालिस्तान की बात करते हुए मिलते हैं। कुछ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मिल जाते हैं। इन किसानों के मन में एमएसपी पर गारंटी की डिमांड कम, केंद्र सरकार को बदलने का जज्बा काफी है। इनमें से कुछ में नरेंद्र मोदी के लिए इतनी नफरत भरी हुई है जैसे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने विरोधी दलों के नेताओं के बारे में रखता है। बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में भी अपने विरोधी दल के नेता के लिए मरने–मारने की बात नहीं होती। यहां तो किसान मरने–मारने की बात भी कर रहे हैं। पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोकने की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन भी इस आंदोलन में शामिल है।

आंदोलन शुरू होने से 2 दिन पहले जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट किसान आंदोलन को सम. र्थन करते आ गया था उससे भी इस संदेह को बल मिला कि यह आंदोलन किसानों के अधिकार के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ज्यादा है। कांग्रेस नेता रमनदीप सिंह मान पर आरोप है कि वो कांग्रेस और किसान नेताओं के बीच कड़ी का काम कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य के हैंडल ने उनके कई ट्वीट्स की कड़ी का थ्रेड बनाकर अपने हैंडल पर डाला हुआ है। इस थ्रेड से पता चलता है कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरह रमनदीप सिंह के साथ मिलकर किसान आंदोलन को खड़ा किया। जब चार साल पहले तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी को लगभग 13 महीने तक बंधक बनाए रखा गया था। धरना– प्रदर्शन और आंदोलन के बहाने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसान संगठनों की ओर से बनाए गए माहौल का ही नतीजा था कि केंद्र सरकार को उन तीन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, जिन्हें कृषि और कृषक समुदाय के लिए क्रांतिकारी माना जा रहा था।

सच्चाई यह है कि पिछली सरकारों ने जो कुछ किसानों की भलाई के लिए किया, वर्तमान सरकार ने उससे बढ़कर ही किया है। आंकड़े इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। ये भी सच्चाई है कि किसानों की भलाई के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी भी है। असल में, जब आंखों में विरोधी चश्मा चढ़ा हो और दिमाग में रटी रटाई स्क्रिप्ट तैर रही हो तो बातचीत से मामला हल कहां होने वाला है? सरकार चाहे जितने भी उपाय और मजबूरियां बता दे, किसान नेताओं को तो अपनी बात पर अड़े रहना है। शायद उनके राजनीतिक आकाओं की ऐसी ही मंशा होगी।

किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पिछले सात दशक से जिस तरह की कृषि नीति देश में अपनायी गयी है, उन नीतियों से किसानों की स्थिति तो नहीं सुधरी है, न ही उनको उनकी उपज का वाजिब दाम ही मिल पाता है। लेकिन किसानों के ही फसलों से कृषि तंत्र पर कब्जा जमाए बिचौलियों और कारोबारियों की आर्थिक सेहत हमेशा ही बल्ले–बल्ले रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार और बिचौलियों को सिस्टम से बाहर करने के लिए ही सरकार तीन नये कृषि कानून लेकर आई थी। लेकिन ये भ्रम फैलाया गया कि नये कानून किसान विरोधी हैं। सरकार ने भी दबाव में आकर कानून वापस ले लिये। जानकारों का मानना है कि, नये कृषि कानून लागू हो गये होते तो किसानों की कई समस्याओं का हल स्थायी तौर पर हो जाता।

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उनका जीवन सुधरे और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ जीवन बिताएं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसानों को भी तनातनी और राजनीति छोड़कर बातचीत से मसला हल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिंसा और उपद्रव से किसानों की छवि तो खराब होती ही है, देश के साधनों और संसाधनों का नुकसान होता है और आम नागरिकों को भी परेशानियां पेश आती हैं। सरकार को सहानुभूति पूर्वक किसानों की व्यावहारिक मांगों को स्वीकार करना चाहिए। शांति और सद्भाव का माहौल ही किसी देश के विकास को गति प्रदान करता है।आशीष वशिष्ठ

दिन–ब–दिन बदतर होती बुजुर्गों की स्थिति

देश में ज्यादातर बजूर्ग नागरिकों की स्थिति दिन–ब–दिन बदतर होती जा रही है। उन्हें अपने जीवनयापन के लिए अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिवार की स्थिति पहले की तुलना में काफी भिन्न हो गई है। परिवार भारतीय समाज की महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन अब परिवारों का स्वरूप भी बदल गया है। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों की बढ़ती संख्या से बुजुर्ग नागरिक अब हाशिये पर आ गए हैं, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। वर्तमान में देश की कुल आबादी का दस प्रतिशत से अधिक हिस्सा बुज्गों का है, जो लगभग 11 करोड़ है 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कुल आबादी का 19.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

केन्द्र सरकार बुजुर्गों की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति ला सकती है लेकिन अभी नीति आयोग ने इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा बुजुर्गों की मदद के लिए जो मसौदा जारी किया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके आधारपर केन्द्र सरकार को नीति बनाने में काफी सहायता मिल सकती है। मसौदेमें बुजुर्गों को मुख्य रूप से चार सेक्टर स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक और डिजिटल रूप से सुरक्षित करने की संस्तुति की गई है। सबसे अधिक चिन्ता की बात बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को लेकर सामने आई है। देशमें 78 प्रतिशत बुजुर्गो के पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। मात्र 18 प्रतिशत बुजुगों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। डिमेनशिया जैसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने वाले बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी प्रकार अन्य बीमारियों से भी वे ग्रसित हैं। परिवार में लोगों की संख्या कम होती जा रही है जिसके कारण बुजुर्गों की सही देखभाल की समस्या बढ़ती जा रही है। साठ वर्ष से अधिक उप्रके बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता प्रभावित हो रही है और वे पराश्रित हो गये हैं। वित्तीय सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को डिजिटल रूप से जागरूक करना आवश्यक हो गया है। जापान, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे कई देशोंमें बुजुर्गोंको दी जानेवाली आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा काफी बेहतर हैं। नीति आयोग ने बुजुर्मों के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा के साथ ही उनके अनुभव और कुशलता को देखते हुए रोजगारके सूजनपर भी जोर दिया है, जो उचित है। सरकार को बुजुर्गों की सुरक्षा और बेहतर जीवनयापन के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय या आयोग बनाना चाहिए। साथ ही रेलवे किराये में छूट की पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल करने की आवश्यकता है बुजुर्ग हमारे देश के सम्मानित नागरिक अवश्य हैं लेकिन उनका जीवन सम्मानजनक नहीं है। इसके लिए सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे। बुजुर्गों का असुरक्षित जीवन अभिशाप बन गया है।

जादुई आवाज ने जीतने वाले अमीन सयानी

अमीन सयानी का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन हो गया, जानें अमीन के बारे में कुछ अनसुनी बातें रेडियो को सुनने वालों के लिए आज बहुत ही बड़ी दुख की खबर सामने आई है।

अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस खबर की पुष्टि अमीन के बेटे रिजील सयानी ने की है। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। परिचित अभिवादन और तुरंत पहचानी जाने वाली आवाज 1952 से 1988 तक रेडियो सीलोन पर हर बुधवार को अनगिनत घरों में प्रसारित होती थी, जो आज भी श्रोताओं के बीच मजबूत पुरानी यादों को जगाती है। अमीन रेडियो पर आने वाले शो गीतमाला को होस्ट करते थे। 30 मिनट के इस रेडियो प्रोग्राम में एक के बाद एक एवरग्रीन गानों से अमीन श्रोताओं का मनोरंजन करते थे।

जादुई आवाज ने जीता दिल

अमीन सयानी की आवाज में इतना जादू था कि लोग रेडियो के आगे बैठकर उनके शो का इंतजार करते थे। इस लेख के जरिए आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आइए अमीन सयानी के बारे में कुछ खास किस्से बताते हैं।

करियर की शुरूआत

ऑल इंडिया रेडियो के मशहूर अना. उंसर अमीन सयानी का बचपन से ही साहित्य में खास लगाव था। इसका खास कारण हैं कि अमीन की मां रहबर नामक समाचार पत्र निकालती थीं और उनके भाई हामिद सयानी भी रेडियो अनाउंसर थे। दरअसल, अमीन भी 1952 में रेडियो सीलोन से अपने करियर की शुरूआत की। 21 दिसबंर 1932 को मुबंई में जन्मे फेमस रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी। वहीं, अमीन का रेडियो से परिचय उनके भाई हामिद ने कराया था। बता दें कि, अमीन ने अपने करियर की शुरूआत इंग्लिश प्रोग्राम से की थी।

फिल्मों में भी कर चुके हैं काम

फिल्मों में भी नजर आ चुके है अमीन, इन फिल्मों में आए नजर अमीन, कत्ल, तीन देवियां, भूत बंगला और बॉक्सर जैसी फिल्मों मे अभिनय कर चुके है। इन फिल्मों में वह शो के प्रेजेंटर के रोल में नजर आए थे।

भारत एक श्रम प्रचुर और पूंजी कम वाला देश

मुंबई। श्रम सुधारों की वकालत करते हुए 16वें वित आयोग के चेयरमैन और नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत के लिए ब ेरोजगारी कोई समस्या नहीं है लेकिन अल्. परोजगार एक समस्या जरूर है। वह यहां दो दिवसीय आइडियाज ऑफ इंडिया समिट–3.0 के समापन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने यह आशा व्यक्त किया कि आगामी दस वर्षों में देश में नौकरियों की समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी वास्तव में भारत की समस्या नहीं है। हमारी समस्या अल्प रोजगार है। इसलिए उत्पादकता कम है। ऐसे में जो एक व्यक्ति जो काम कर सकता है वह अकसर दो या तीन लोगों द्वारा किया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि नौकरियों की वास्तविक चुनौती अच्छी तनख्वाह वाली उच्च उत्पादकता वाली नौकरियां पैदा करना है। अर्थव्यवस्था की भाषा–भारएक श्रम–प्रचुन पूंजी कम वाला देश है।

उन्होने कहा कि हमें ऐसी स्थिति मिली है जहां अधिकांश पूंजी बहुत कम श्रमिकों के साथ काम कर रही है। कहीं दूसरी ओर कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों में श्रमिको की एक बड़ी संख्या है। बहुत सारे श्रमिक हैं जो बहुत कम पूंजी के साथ काम कर रहे हैं। देश को अभी श्रम और व्यापार कानूनों को सुधारने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भारत में आम सहमति बनाना लोकतांत्रिक सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिससे कानून पारित करना धीमी प्रक्रिया बन जाती है। सुधारों के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यामों और बैंकों का निजीकरण कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं जिन्हें किए जाने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर हम एक अच्छी स्थिति में हैं। ये समस्याएं हैं लेकिन मुझे लगता है कि आगामी दस वर्षों में इन्हें हल कर लेंगे।

अरविन्द पनगढ़िया
चेयरमैन, वित्त आयोग

मंत्री ने छात्रावासों का किया औचक निरीक्षण

❑ **अनियमितताएं मिलने पर छात्रावास अधीक्षक सस्पेंड**

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को टोंक में देवली और निवाई में राजकीय अंबेडकर छात्रावासो का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान देवली स्थित छात्रावास में कोई छात्र उपस्थित नहीं पाया गया, वहीं निवाई में निरीक्षण के दौरान 4 छात्र फर्जी रूप से उपस्थित मिलें। जिस पर गहलोत के आदेशानुसार छात्रावास अधीक्षक राजेंद्र चौधरी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि दुर्गापुरा ढाणी स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास के औचक निरीक्षण के दौरान भी कोई छात्र उपस्थित नहीं पाया गया। छात्रावास में 50 स्टूडेंट्स के लिए स्वीकृति है इनमे से 38 स्टूडेंट का हॉस्टल में नामांकन है एवं रजिस्टर चेक करने पर 25 बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर में मिली लेकिन हॉस्टल में एक भी स्टूडेंट नहीं था। इस दौरान वॉर्डन भागचंद चौधरी से इस सम्बन्ध में जानकारी ली गई। इसके बाद अविनाश गहलोत राजकीय अंबेडकर छात्रावास निवाई के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। यहां उन्हें 13 छात्रों में से 4 फर्जी रूप से रहते हुए पाए गए।

उन्होंने बताया कि छात्रावास अधीक्षक राजेंद्र चौधरी ने रजिस्टर में 39 बच्चों का रजिस्ट्रेशन दिखाया हुआ था। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमिताओं की जाँच के लिए राजेन्द्र कुमार शर्मा, उप निदेशक (छात्रावास), मुख्यालय को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने छात्रावास में रसोई, शौचालय और परिसर की साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन संपन्न

❑ **कर्नाटक के संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में एक 8 वर्षीय बच्चे का पाठ**

बेंगलुरु। सम्मेलन में कर्नाटक के नागरिकों के बीच संविधान के वास्तविक सार के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट सहयोगियों आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे और समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा के साथ शनिवार, 24 फरवरी को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में दो दिवसीय संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन '24 का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में संविधान के वास्तविक सार के बारे में कर्नाटक के नागरिकों को जागरूक करने और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

संविधान सम्मलेन प्रारम्भ

दर्शकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ''देश में यह प्रचार किया जा रहा है कि संविधान केवल दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया है और यह देश की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह का झूठा प्रचार करते हैं वे संविधान के मूल मूल्यों के खिलाफ हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की वकालत करते हैं।

मुस्लिम निकाह–तलाक रजिस्ट्रेशन वाला कानून निरस्तीकरण की मिली मंजूरी

❑ **बाल विवाह पर लगेगी रोक : सीएम**

गुवाहाटी। यह अधिनियम वर्ष 1935 में अंग्रेजों द्व ारा लाया गया था। यह असम के मुस्लिमों के लिए विवाह पंजीकरण और तलाक के नियम बनाता था। इसके अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, जिसे सरकार अधिकृत कर दे, मुस्लिम निकाह को पंजीकृत कर सकता था।

असम ने वर्ष 1935 में बनाए गए मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम (Muslim Marriages and Divorces Registration Act 1935) को रद्द कर दिया है।

इसकी जानकारी सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा है कि इससे अंतर्गत शादी की कानूनी आयु ना पूरी करने वालों का भी निकाह हो रहा था।

सीएम हिमंता ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "23 फरवरी, 2024 को असम कैबिनेट ने दशकों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भले ही दूल्हा और दुल्हन की उम्र 18 और 21 ना हुई हो, जैसा कि कानूनन होना चाहिए, के विवाह का पंजीकरण भी इसके अंतर्गत

हो रहा था। यह निर्णय असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" इससे पहले असम सरकार में मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने इस विषय में मीडिया से बात की। उन्होंने मीडिया को बताया, "असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, जिसके आधार पर अब तक 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार राज्य में मुस्लिम निकाहों का पंजीकरण कर रहे थे और तलाक का निर्णय कर रहे थे, उसे निरस्त कर दिया गया है। आज की कैबिनेट बैठक में इस अधिनियम को हटा दिया है।"

'हर हर गंगे' उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

प्रयागराज। संगम नगरी में माघ मेले के पंचम स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर शनिवार को 'हर हर गंगे' उद्घोष के बीच शाम छह बजे तक लगभग 38.20 लाख लोगों ने गंगा और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवासी एक महीने का कल्पवास पूरा कर अपने अपने घरों को लौटने लगे।

माघ मेला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह से ही बादल छाए रहने और ठंडा मौसम रहने के बावजूद शनिवार शाम छह बजे तक करीब 38.20 लाख लोगों ने गंगा और संगम में स्नान किया। उनके मुताबिक, तड़के से ही स्नानार्थियों का माघ मेला क्षेत्र में आना जारी रहा जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। उन्होंने बताया कि स्नानार्थियों की सुविधा के लिए घाटों की लंबाई 6800 फुट से बढ़ाकर 8000 फुट कर दी गई है और कुल 12 घाट बनाए गए हैं एवं सभी घाटों पर पर्याप्त संख्या में वस्त्र बदलने की सुविधा स्थापित की गई है।

पुलिस उप महानिरीक्षक (माघ मेला) राजीव नारायण मिश्र के अनुसार, मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और पूरे मेला क्षेत्र में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित कैमरे लगाए गए हैं।

माघ मेला से मुंबई अपने आश्रम के लिए प्रस्थान की तैयारी कर रहे अवधूत भगवान राम के शिष्य आशीष महाराज ने बताया कि माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर अन्न वस्त्र दान करने का विशेष महत्व है। उनके मुताबिक, इस स्नान के साथ लोग महीने भर का कल्पवास पूरा कर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। माघी पूर्णिमा पर मेला क्षेत्र और नगर में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा पूड़ी सब्जी, हलवा पूड़ी आदि का वितरण किया जा रहा है। वहीं, माघ मेला क्षेत्र में लगे साधू संतों के शिविर में व्यापक स्तर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस बीच, कल्प. वासियों और उनके घरेलू सामान आदि को लेकर मेला क्षेत्र से बाहर निकल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली व पिक–अप वाहनों के चलते झूंसी पुल, नैनी पुल और बांगड़ धर्मशाला चौराहा पर दोपहर से ही भारी जाम लगा है। यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यातायात पुलिस के जवानों को जाम खुलवाने के काम पर लगाया गया है।.

समाज और न्याय व्यवस्था के मुँह पर तमाचा फिल्म 'भक्षक'

फिल्म की कहानी जैसे–जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे–वैसे ये हमारे समाज, पत्रकारिता, मानवता और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाती है और उन्हें चुनौती देती है। फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जिन्हें निर्देशक पुलकित ने बखूबी दशार्या है।

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की फिल्म 'भक्षक' नेटफिलक्स पर रिलीज हो गई है। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म और स्टार कास्ट की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म में भूमि के अलावा आदित्य श्रीवास्तव, साई ताम्हणकर, संजय मिश्रा, तनीषा मेहता, विभा छिब्बर और दुर्गेश कुमार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं।

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी में एक स्वतंत्र टीवी रिपोर्टर वैशाली सिंह (भूमि पेडनेकर) और उसके सहयोगी भास्कर (संजय मिश्रा) के इर्द–गिर्द घूमती है। ये दोनों अनाथालय के बंद दरवाजों के पीछे लड़कियों के साथ हो रहे गलत कामों का पदार्फाश करने में जुटे हुए हैं। ये काम एक बड़े और शक्तिशाली शख्स बंसी साहू (आदित्य श्रीवास्तव) द्वारा किया जा रहा है। फिल्म में नाबालिग अनाथ लड़कियों को साहू के चंगुल से बचाने की कहानी दिखाई गयी है। ऐसे मामलों को उजागर करने के दौरान एक पत्रकार को कैसे राजनीतिक डर, धमकियों और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है।

कैसी है फिल्म?

फिल्म की शुरूआत बेहद ही परेशान करने दृश्य से की गयी है। ये दृश्य बहुत लोगों के दिमागों में छप सकता है और कई दिनों तक आपको इससे निकलने में मुश्किल हो सकती है। भक्षक में कड़े दृश्यों के साथ कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म की कहानी जैसे–जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे–वैसे ये हमारे समाज, पत्रकारिता, मानवता और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाती है और उन्हें चुनौती देती है। फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जिन्हें निर्देशक पुलकित ने बखूबी दशार्या है। भूमि पेडनेकर ने एक पत्रकार का किरदार बखूबी निभाया है और अन्य कलाकारों ने भी अपने किरदारों की बेहतरीन पेश किया।

विलुप्त होती मातृभाषाओं को रक्षित किए जाने की आवश्यता

आज विश्व में ऐसी कई भाषाएं और बोलियां हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है। लोकभाषाओं की चिंता इसलिए जरूरी है कि ये हमारी विरासत का एक भाग हैं और हमारी थाती हैं और इनमें जो भी कुछ सुंदर और श्रेष्ठ रचा जा रहा है, उसे सहेजकर रखा जाना चाहिए। यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना। मातृभाषा के माध्यम से इंसानों को आपस में जोड़ना एवं सौहार्द स्थापित करना। यूनेस्को द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा से बांग्लादेश के भाषा आन्दोलन दिवस को अन्तरराष्ट्रीय स्वीकृति मिली, जो बांग्लादेश में सन् 1952 से मनाया जाता रहा है। बांग्लादेश में इस दिन एक राष्ट्रीय अवकाश होता है। 2008 को अन्तरराष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के महत्व को फिर दोहराया है।

2024 की थीम ह्यबहुभाषी शिक्षा अंतर–पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ हैह्ण। आज 250 मिलियन बच्चे और युवा अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं और 763 मिलियन वयस्क बुनियादी साक्षरता कौशल में निपुण नहीं हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृतियों एवं बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हर दो सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो जाती है और विश्व एक पूरी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत खो देता है।

जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं, वही व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसे सीखने के लिए उसे किसी कक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मानव समाज में कई दफा हमें मानवा. धिकारों के हनन के साथ–साथ मातृभाषा के उपयोग को गलत भी बताया जाता रहा है। ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश में जब 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था। लेकिन इस क्षेत्र में बांग्ला और बंगाली बोलने वालों की अधिकता ज्यादा थी और 1952 में जब अन्य भाषाओं को पूर्वी पाकिस्तान में अमान्य घोषित किया गया तो ढ़ाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदा. लन छेड़ दिया।

आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसमें कई छात्रों की मौत हो गई। अपनी मातृभाषा के हक में लड़ते हुए मारे गए शहीदों की ही याद में मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आज विश्व में ऐसी कई भाषाएं और बोलियां हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है। लोकभाषाओं की चिंता इसलिए जरूरी है कि ये हमारी विरासत का एक भाग हैं और हमारी थाती हैं और इनमें जो भी कुछ सुंदर और श्रेष्ठ रचा जा रहा है, उसे सहेजकर रखा जाना चाहिए।

यूनेस्को के अनुसार भाषा केवल संपर्क, शिक्षा या विकास का माध्यम न होकर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है, उसकी संस्कृति, परम्परा एवं इतिहास का कोष है। अगर हम भारत की बात करें तो यहां हर कुछ कदम पर हमें बोलियां बदलती नजर आएंगी। 85 संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के तीन हजार विशेषज्ञों के पीपुल्स लिंग्युस्टिक सर्वे आफ इंडिया (पीएलएसआई) के अध्ययन के अनुसार पिछले 50 वर्षों के दौरान 780 विभिन्न बोलियों वाले देश की 250 भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं। इनमें से 22 अधिसूचित भाषाएं हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 10 हजार से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 122 भाषाएं हैं। बाकी 10 हजार से कम लोगों द्वारा बोली जाती है। आयरिश भाषाई विद्वान जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बाद पहली बार 1898–1928 के बीच भाषाई सर्वे किया गया है। आजाद भारत में पहली बार किए गए इस पहले सर्वे में चार वर्ष लगे। इस रिपोर्ट के अनुसार भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत में अरुणाचल प्रदेश सबसे समृद्ध राज्य है, वहाँ 90 से अधिक भाषाएँ बोली जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान है, जहाँ 50 से अधिक भाषाएँ बोली जाती है। 47 भाषाओं के साथ ओडिशा चौथे स्थान पर है। इसके विपरीत गोवा में सिर्फ तीन भाषाएं बोली जाती हैं तो दादर और नगर हवेली में एक भाषा ह्णगोरपाह्ण है, जिसका अब तक कोई रिकार्ड नहीं है।

भारत में यह दिवस विशेष रूप से उन जनजातीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है जहाँ बच्चे उन विद्यालयों में सीखने के लिये संघर्ष करते हैं जिनमें उनको मातृभाषा में निर्देश नहीं दिया जाता है। ओडिशा में केवल 6 जनजातीय भाषाओं में एक लिखित लिपि है, जिससे बहुत से लोग साहित्य और शैक्षिक सामग्री तक पहुँच से वंचित हैं। सरकार ने ह्यभाषा संगमह्ण कार्यक्रम शुरू किया है, जो छात्रों को अपनी मातृभाषा सहित विभिन्न भाषाओं को सीखने और समझने के लिये प्रोत्साहित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना भी है। सरकार ने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भी स्थापित किया है, जो भारतीय भाषाओं के अनुसंधान और विकास हेतु समर्पित है। मातृभाषाओं की र क्षा हेतु कई राज्य–स्तरीय पहलें भी हैं। उदाहरण के लियेओडिशा सरकार ने ह्यअमा घरह्ण कार्यक्रम शुरू किया है, जो आदिवासी बच्चों को आदिवासी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करता है।

करीब 400 से अधिक भाषाएं आदिवासी और घुमंतू व गैर–अधिसूचित जनजातियाँ बोलती हैं। यदि भारत में हिंदी बोलने वालों की तादाद लगभग 40 करोड़ है तो सिक्किम में माझी बोलने वालों की तादाद सिर्फ 4 है। पूर्वात्तर के पाँच राज्यों में बोली जाने वाली करीब 130 भाषाओं का अस्तित्व खतरे में हैं। असम की 55, मेघ ालय की 31, मणिपुर की 28, नागालैंड की 17 और त्रिपुरा की 10 भाषाएं खतरे में हैं। हाल ही में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तकरीबन हजारों साल से बोली जाने वाली एक आदिवासी भाषा ह्यबोह्य हमेशा के लिए विलुप्त हो गई । भारत में मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिये नरेन्द्र मोदी सरकार प्रयासरत है।

उन्होंने उच्च शिक्षा के स्तर पर भी बहुभाषिकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्वीकार किया है। भारतीय वैज्ञानिक सी.वी.श्रीनाथ शास्त्री के अनुभव के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले की तुलना में भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े छात्र, अधिक उत्तम वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। महात्मा गाँधी ने कहा था, ह्लविदेशी माध्यम ने बच्चों की तंत्रिकाओं पर भार डाला है, उन्हें रट्टू बनाया है, वह सृजन के लायक नहीं रहे। विदेशी भाषा ने देशी भाषाओं के विकास को बाधित किया है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम के शब्दों का यहां उल्लेख आवश्यक हो जाता है कि ह्लमैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना, क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।

सशक्त भारत–निर्माण एवं प्रभावी शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने अपने से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिये 2021–22 के शैक्षणिक सत्र के लिये लिया है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जा रही है। नवंबर 2020 में, शिक्षा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें कॉलेजों को मातृभाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा देने की अनुमति दी गई थी। एआईसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की शिक्षा दिये जाने के लिए बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु सहित आठ क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य–सामग्री के अन. ुवाद पर काम शुरू कर दिया है। भारत सुपर पावर बनने के अपने सपने को साकार कर सकता है। इस महान उद्देश्य को पाने की दिशा में विज्ञान, तकनीक और अकादमिक क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान करने के अभियान को तीव्रता प्रदान करने के साथ मातृभाषा में शिक्षण को प्राथमिकता देना होगा। मातृभाषा जब शिक्षा का माध्यम बनेगी तो मौलिकता समाज में रचनात्मकता का अभियान छेड़ेगी। भाषा और गणित को नई नीति में प्राथमिकता मिलना बच्चों में लेखन के कौशल और नवाचार का संचार करेगा। सृजनात्मक गतिविधियों का वातावरण पैदा करेगा। मातृभाषा सम्पूर्ण देश में सांस्कृ तिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। भारत का परिपक्व लोकतंत्र, प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्व भर में एक उच्च स्थान रखता है, उसी तरह भारत की गरिमा एवं गौरव की

प्रतीक मातृ भाषाओं को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए।

हार के बावजूद अमेठी का मैदान छोड़ने के मूड़ में राहुल गांधी

कांग्रेस नेत्री और गांधी परिवार की बेटी प्रियंका वाड्रा गाँधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कांग्रेस आलाकमान भले ही चुप्पी साधे हुए है, लेकिन राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस अध्य क्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने काफी कुछ साफ कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अमेठी पहुंची तो लगे हाथ कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का संकेत देकर गाँधी परिवार की अमेठी–रायबरेली वाली सियासत को फिर जिंदा कर दिया है। यह दोनों वह संसदीय क्षेत्र हैं जिसका गांधी परिवार से काफी लगाव रहा है। जब कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में उखड़ गई तब भी अमेठी रायबरेली में उसकी जड़ें जमी रही थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर अमेठी से गाँधी परिवार का सफाया हो गया था ले. किन यहां कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। गांधी परिवार भावनात्मक रूप से अपने आप को अमेठी से जोड़कर बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखता है। खरगे ने राहुल गांधी की अमेठी से लोकसभा उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा नहीं की मगर अमेठी की जनता से यह जरूर कह दिया कि राहुल गांधी कल भी आपके साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इससे पूर्व सोनिया गांधी ने भी रायबरेली की जनता को लिखे भावनात्मक पत्र में अमेठी का जिक्र करके इसे गांधी परिवार के करीब बताया था।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अमेठी से गांधी परिवार के करीबी रिश्ते को लेकर सोनिया गांधी के 26 साल पहले दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी भी अमेठी से दिल का करीबी रिश्ता होने की बात को आज दोहरा रहे हैं। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने के इरादों का साफ संदेश देते हुए खरगे ने इस संसदीय क्षेत्र की जनता से यह कहने से भी गुरेज नहीं किया कि भले ही क्षेत्र को कोई सांसद मिल सकता है, मगर राहुल गांधी जैसा इंसान उन्हें कहां मिलेगा। मगर इससे इत्तर अमेठी से चुनाव लड़ना गांधी परिवार के लिये अब आसान नहीं रह गया है। पिछले पांच वर्षों में अमेठी काफी बदल गया है। अमेठी की मौजूदा सांसद और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अमेठी की जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है। खास बात यह रही कि मल्लिकार्जुन खरगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में जब अमेठी पहुंचे तो राहुल गांधी की मौजूदगी में वहां हुई एक जनसभा में अमेठी के रास्ते उत्तर प्रदेश के मैदान में कांग्रेस के डटे रहने का एलान किया गया। अमेठी वासियों के साथ गांधी परिवार के निकट रिश्तों का जिक्र करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक शायरी की पंक्तियों–

अगर तलाश करे कोई मिल ही जाएगा,
मगर तुम्हारी तरह कौन हमको चाहेगा,

के द्वारा राहुल के अमेठी के चुनावी रण में ताल ठोंकने की घोषणा की।

खरगे ने यह भी कहा कि अमेठी को भले ही कोई सांसद मिल जाए मगर राहुल जैसा सहज और सहृदयी इंसान कहां मिल पाएगा। शायरी की इन पंक्तियों के बाद खरगे ने कहा कि अमेठी के लोग भी यही बोलते हैं और राहुल गांधी को चाहते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर भले ही सीधे कोई टीका–टिप्पणी नहीं की लेकिन अमेठी और यहां के लोगों के साथ गहरे प्यार और जुड़ाव का इजहार करते हुए सदैव उनका आभारी रहने की बात कह पुराने रिश्ते की डोर को आगे बढ़ाते रहने का संदेश दिया। अमेठी से रिश्ते की बुनियाद नई नहीं बल्कि दशकों पुरानी है।

खैर, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी और उससे पहले सोनिया गांधी के रिश्ते की बुनियाद अमेठी से नई नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। इसका संदेश आने के बाद गांधी के पूरे देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीति में 1998 में पहली बार अमेठी आई सोनिया बयान को पढ़ा। इसमें सोनिया ने कहा था– ह्यमेरे मन में अमेठी के लोगों के प्रति अटूट प्रेम और आदर है। अमेठी मेरे पति की कर्मभूमि थी। उनके दिल में अमेठी के भाई–बहनों के लिए कितना प्यार और समर्पण था मैंने इसे गहराई से महसूस किया है। आपने हर हालात में हमारा साथ दिया है। ये बात हम कभी भूल नहीं सकते। खरगे ने कहा कि सोनिया गांधी की यही बात फिर राहुल गांधी ने दोहराई है। आपके साथ उनका गहरा संबंध और प्रेम है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बेलाग बयान का सार स्पष्ट है कि वर्तमान में केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी 2019 की पराजय के बावजूद अमेठी का चुनावी रण नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल, जल्द ही अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस निर्णय ले लेगी, मगर सवाल यह भी है कि यदि सपा–कांग्रेस में गठबंधन नहीं भी होता है तो क्या समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार को पहले की तरह वॉकओवर दे सकती है। सपा कई बार गांधी परिवार के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने का कारमाना कर चुकी है।

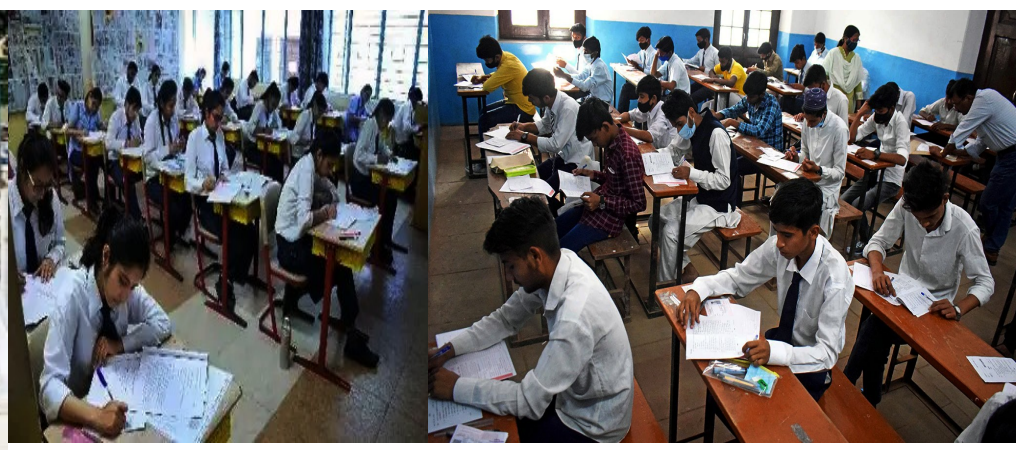

यूपी बोर्ड परीक्षा में अपनी किस्मत लिखते परीक्षार्थी

शीर्ष न्यायालय का फैसला एक नजीर ही नहीं न्यायाधीशों के लिए सबक भी

गृहस्थ जीवन में गृहिणियों को भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इनके महत्व को कम करके आंका जाना किसी भी रूप में उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में स्र्वोच्च न्यायालय का कहना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि गृहिणी की भूमिका वेतनभोगी परिवार के सदस्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। एक दुर्घटना मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकान्त और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ का दर्घटना में मृत महिला के परिजनों को मुआवजा बढ़ाने का निर्देश न्यायसंगत है।

पूर्व में एक मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने मृत महिला के परिजनों, उनके पति और नाबालिग बेटे को 2.5 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया था।

परिवार ने अधिक मुआवजे के लिए उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिसे महिला के गृहिणी होने के आधार पर खारिज कर दी गई थी। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि एक गृहिणी की आय को दैनिक मजदूर से कम कैसे माना जा सकता है। शीर्ष न्यायालय की टिप्पणी अन्य न्यायालयों के लिए नसीहत है कि फैसला देते समय अपने विवेकाका भी परिचय दें। इसके साथ ही पीठने मुआवजा बढ़ाकर छह लाख कर दिया और वाहन मालिक को छह सप्तह के अन्दर महिला के परिजन को भुगतान करने का निर्देश दिया।

पीठ का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि महिला जिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन से यात्रा कर रही थी उसका बीमा नहीं था इसलिए मुआवजा देने का दायित्व वाहन मालिकपर है।

अकसर दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे के मामलों में संस्थानों, वाहन मालिकों और बीमा कम्पनियों की हीला हवाली और कानूनी दावपेंच के सहारे बचने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। लेकिन मामला यदि न्यायालय तक पहुंचता है तो यह न्यायाधीशों का उत्तरदायित्व है कि वे कानून के साथ मानवीय संवेदना को भी आधार बनाएं। शीर्ष न्यायालय का फैसला पीड़ित पक्ष के हित में एक नजीर है। साथ ही न्यायाधीशोंके लिए सबक भी है।

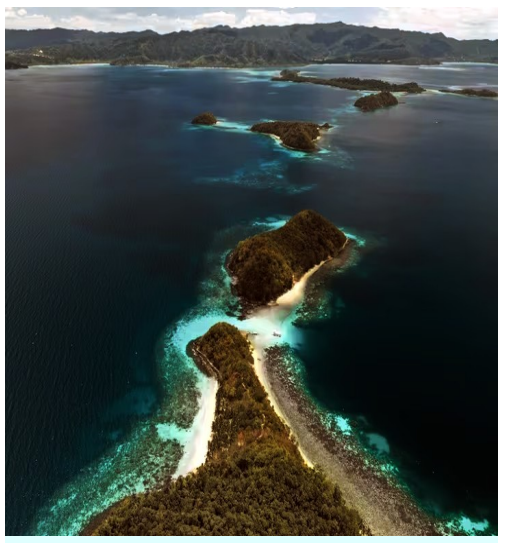

दूर हो रही महासागर के नीचे की प्लेट

हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह बहुत सी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जिनकेऊपर महाद्वीप और महासागरों के तल बने हैं। इन टेक्टोनिक प्लेटों गतिविधियां होने पर ही दुनिया में भूकंप और कई जगह ज्वालामुखी की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। नए शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि न्यूजीलैण्ड से लेकर जापान के बीच प्रशांत महासागर के नीचे की महासागर प्लेट टूट कर दूर हो रही है। अभी तक वैज्ञानिक सबसे ज्यादा ध्यान महाद्व ीपों की प्लेटों पर देते थे, लेकिन इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि प्रशांत महासागर के नीचे पृथ्वी की सतह के अंदर बहत सारी कडक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर खिंच रही हैं। पृथ्वी के बाहरीखोल, जिससे हम. लिथोस्फियर या स्थलमंडल कहते हैं.कई कड़क प्लेटों से बना है। यह प्लेट एकअर्द्धतरल पदार्थ केऊपर तैर रही हैं। इस तरल पदार्थ एस्थेनोस्फयर कहते हैं। इन प्लेटों की खास बात यही है कि ये इधर उधर,दाएं बाएं यहां तक कि एक दूसरे के ऊपर नीचे भी होती रहती हैं। टोरेंटोयूनिवर्सिटी के जियो साइंटिस्ट ने पता लगया है कि ये प्रशांत महासागर केनीचे की प्लेटों में बहत बड़ी दरारें हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी होनेके साथ हजारों मीटर गहरी भी हैं। महाद्वीपीय प्लेट के आंतरिक हिस्सों अंदरहोने वाली पृथ्वीं के सतह के नीचे होने वाली इस विकृति से वैज्ञानिक बहुतहैरान हैं। जियोफिजिकल रिसर्च लैटर्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन केशोधकर्ताओं का कहना है कि वे यह तो जानते हैं कि इस तरह की विकृति महाद्वीपीय प्लेट के अंदर होती रहती हैं, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था किऐसा महासागर की प्लेटों में भी हो रहा है।

वैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेट कोटेबल पर रखे कपड़े की तरह समझाते हैं, जो मुड़ सकता है। माना जाता है कि महासागर के नीचे के प्लेट ज्यादा मोटी होती हैं और उन्हें ज्यादा मजबूत होना चाहिए। लेकिन भूकंपीय आंकड़े और अन्य जानकारी से पता चलता है कि पठार कमजोर होते हैं।

हम हिंदू, हिन्दुस्तान हमारा

जपो निरंतर एक जबान, हिंदी, हिंदू,हिन्दुस्तान' प्रताप नारायण मिश्र जी की ये पंक्ति आज भी राष्ट्रवादियों का आह्वान करती है। राष्ट्रवाद उत्थान,राष्ट्रीय गौरव और सुसुप्त भारतीयों के जागरण का आह्वान करती है। ये उद्घोष राष्ट्रीय जीवन के लिए अत्यावश्यक है। राष्ट्रवाद की धारणा राष्ट्र की एकता,अखंडता,सुरक्षा, विकास तथा राष्ट्र जीवन की पहली आवश्यक शर्त है। जिस देश में राष्ट्रवाद की भावना नहीं वह राष्ट्र एक इकाई होते हुए भी आन्तरिक भावना के आधार पर विभाजित होता है।

हमें राष्ट्रवाद को जीवित रखने के लिए एक मंत्र को जपना होगा कि 'हम हिंदू,हिन्दुस्तान हमारा' इसे प्रचारित और प्रसारित करना होगा।

इस मंत्र से लोगों को आपत्ति हो सकती है। कहेंगे कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते है। मुसलमानों को भड़काने के लिए वाक् योद्धा तिकड़म लगायेंगे। दंगे कराने की धमकी देंगे।

हमारे देश के राजनीतिक दलों में तथा राजनेताओं में राजनीतिक अनुशासन हीनता है। राहुल गाँधी राजनीति के वृक्ष का कच्चा फल है।

हमें इतिहास की सहायता लेनी चाहिए इस राजनीतिक उन्माद को दूर करने लिए जो राष्ट्रवाद की भावना के खिलाफ है। विशेषकर मुसलमानों को समझाने के लिए राष्ट्रवाद के लिए उक्त मंत्र का जाप करना चाहिए।

'हिंदी' शब्द फारसी भाषा का है। फारस यानी ईरान और यहाँ के निवासी मुसलमान है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिन्धु शब्द से हुई। इसी का फारसी रूपांतरण हिंदी है। फारसी में हिंदी की स ध्वनि का उच्चारण ह करते है। इसका प्रभाव राजस्थानी भाषा पर है। राजस्थान के मारवाड़, मेरवाड़ा क्षेत्र की बोली में स को ह बोलते है। सड़क को हड़क बोलते है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब में होता है।

ईरान के बादशाह नौशेरवाँ के हकीम बजरोया ने पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद किया। इस अनुवाद की भूमिका बादशाह के मंत्री बुजर्च मिहर ने लिखी। भूमिका में कहा गया कि यह अनुवाद जबाने–हिंदी से किया गया।

तैमूरलंग के पोते शरफुद्दीन यज्दी ने अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। अमीर खुसरों ने भारतीय मुसलमानों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ईरानी लोगों ने हिन्दू और हिन्दुस्तान नाम दिया। सिन्धु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिन्द प्रदेश कहा। कालांतर में यहाँ के निवासियों को हिन्दू कहा।

ये सारे नाम मुसलमानों ने दिये। हमारे पूर्वज तो आर्य थे। प्राचीन संस्कृति में यहाँ की नारियां पति को आर्य कहती थी। संस्कृत में आर्य शब्द का जिक्र है। जब आर्यावर्त्त के लोगों ने ये सारे मुसलमानों ने दिये। लोगों ने अपना लिए तो मुसलमानों को आज परेशानी क्यों है। जब हम गर्व से कहते है हम हिंदू है हिंदुस्तान हमारा तो परेशानी का कारण होना नहीं चाहिए। मुसलमानों के दिये नामों को वसुधैव कुटुम्बकम के मंत्र से ग्रहण किया।

हिन्दू शब्द वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी वैदिक भावना का प्रतिनिधि शब्द है। हिंदू एक जीवन दर्शन है, जीवन शैली है। मुसलमानों को तो गर्व करना चाहिए हिन्दुस्तान जैसी गौरवमयी धरा इनकी अपनी है।

हिंदू धर्म का अवतार शब्द नहीं है। धर्म तो हमारा सनातन है। हिंदू संतुलित,सद्भाव,समरसता का भावपूर्ण शब्द है। जो यहाँ के निवासियों का प्रतिनिधि है। धर्म तो नियामक तत्व है। धर्म के बिना राजनीति विधवा है। संविधान तो बाद में बना है। पहले धर्म ही संविधान था। धर्म का मतलब पूजा आस्था की संकुचित प्रचलित पद्धति का नाम नहीं है। धर्म समाज का नियामक है। धर्म आधारित समाज और राजनीति ही राष्ट्र के निर्माता है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाले समाज विद्रोही है। धर्म धृ धातु से बना जिसका अर्थ है धारण करना। कर्तव्य ही धर्म है। ये ही धारण योग्य है।

आर्यों की संस्कृति सभ्यता के वाहक होने के नाते आज हमारा धर्म है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम को आगे बढ़ायें। राष्ट्रवाद के पोषक तत्वों को फैलाए। मुसलमानों को घबराना नहीं चाहिए। हम एक भी संस्कृति के वाहक है। राजनेताओं की स्वार्थपरता को जीवन का केन्द्र न बनाये।ऐतिहासिक भौगोलिक बदलाव को स्वीकार वर्तमान समाज की नई दिशा में योगदान दे। राजनीतिक रोटियों को सिकने में खुद को जलाये नहीं। नेताओं की राजनीतिक अनुशासन हीनता देश के लिए खतरा है। इसलिए सभी को राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाना चाहिए। हम हिंदू है, हिन्दुस्तान हमारा है।

ज्ञानीचोर
रघुनाथगढ़,सीकर राज.

सभी संकल्पों को सिद्ध करके मोदी ने देश की जनता का दिल

वर्ष 2024 के आम चुनाव सन्निकट हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक एवं धमाकेदार जीत के प्रति आश्वस्त है। एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी एक नयी पारी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल अगले एक हजार वर्षो के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। इस अवधि में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ विश्वगुरु भी बन सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के दो कार्यकाल की समीक्षा करें तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी सरकार द्वारा उठाये गये हर कदम एवं उनकी हर बात राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ाये गये अनूठे, परिवर्तनकारी एवं सकारात्मक कदम रहे हैं। 2014 से पहले के भारत में भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टिकरण की ही बात सामने आती थी लेकिन अब विकास, अविष्कार और नवाचार की बातें हो रही हैं, जिनमें नये भारत, सशक्त भारत की जड़ें गहरी हुई हैं। मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्ष भारतीय इतिहास में सबसे सुदृढ़ एवं युगांतरकारी रहे हैं। हम सब इतिहास के उस स्वर्णिम काल के गवाह बनने के साक्षी बने हैं। यह सब मोदी के करिश्माई एवं चमत्कारी व्यक्तित्व से ही संभव हो पाया है। करिश्मा किसी व्यक्ति विशेष का एक निश्चित गुण होता है जो अपवाद होता है और जिसके आधार पर वह स्वीकार्यता हासिल कर शासन करता है। लिंकन, चर्चिल, रूसवेल्ट और जॉन एफ केनेडी महान राजनेता थे, जो अपने करिश्माई व्यक्तित्व और प्रभामंडल के लिए जाने जाते थे और इसका उपयोग उन्होंने अपने देश को मजबूत करने के लिए किया। मोदी इसी श्रेणी के इन सबसे आगे निकलते हुए विलक्षण क्षमताओं एवं मौलिक विशेषताओं वाले विरल नेता हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एवं सभी विपक्षी दल अपनी–अपनी चालें चल रहे हैं। भाजपा एवं इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में अब हर दिन चुनावी रणनीति को लेकर नये गठबंधन हो रहे हैं तो बने हुए गठबंधन टूट रहे हैं, अनेक नेता दलों के पाले बदल रहे हैं, एक दूसरे को मात देने का दौर चल रहा है, सब अपनी–अपनी व्यूह रचना बना रहे हैं। भाजपा ने स्वयं की 370 एवं उसके गठबंधन की 400 सीटों का लक्ष्य बनाया है। इंडिया गठबंधन एवं विभिन्न राजनीतिक दल भी जीत की संभावनाओं को लेकर जुटे हैं। राजनीति पल–पल नया आकार लेती है, इसलिये राजनीति में सही वक्त पर सही ढंग से इस्तेमाल करने का हुनर होना अपेक्षित होता है, जो अच्छा चल रहा है उसे बिगाड़ना आना चाहिए और जो बिगड़ रहा है उसे सुधारना आना चाहिए। इसी को कहते हैं राजनीति। इसी राजनीति के महारथी के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा की रणनीति ती क्ष्ण एवं प्रभावी बनकर सामने आ रही है ताकि धमाकेदार चुनाव परिणाम तक पहुंचा जा सके। मोदी की करिश्माई राजनीति का ही परिणाम है कि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को इंडिया गठबंधन से छीन लिया गया है। कांग्रेस के अशोक चव्हान को भाजपा में शामिल करके राज्यसभा में भेज दिया है। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की स्वर सुनाई दे रहे हैं। मायावती और चंद्रबाबू नायडू को विपक्ष में जाने से रोक दिया गया है। शिवसेना और राकांपा की दो फाड़ कर दी गयी है। श्रीराम मन्दिर उद्घाटन से हिन्दू वोटों को प्रभावित किया गया है, वही 'भारत रत्न' की घोषणा से आम चुनावों को प्रभावित करने का राजनीतिक कौशल सामने आया है।

मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि आगामी चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के बनते दृ श्यों को देखकर समूचा विपक्ष बौखलाया हुआ या किंकर्तव्यविमूढ़ दिखाई दे रहा है। यह स्थिति बनने का मूल कारण जहां मोदी का ऐतिहासिक एवं सफल दो कार्यकाल हैं, वहीं आगामी चुनाव को लेकर उनकी रणनीति एवं राजनीतिक कौशल है। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की विशेषताओं में प्रमुख हैं कि वे दूरदृष्टि र खते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। वे अपने एजेंडे को लेकर निर्णायक और स्पष्ट हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह अपने भीतर देखते हैं एवं जनता से सीधा संबंध स्थापित करते हैं। उन्होंने सिर्फ भौतिक–आर्थिक विकास के संदर्भ में ही विकास की बात नहीं की बल्कि विकास का लाभ समाज के निचले तबके और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये योजनाएं एवं नीतियां बनाईं ताकि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए और अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुद्धार को बल दिया, जो सकारात्मक सभ्यता के साझा मूल्यों और इन मूल्यों में गर्व की भावना पर आधारित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश के लिए एक उचित स्थान बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास एक सुस्पष्ट दृष्टि है कि आजादी के 75वें या 100वें साल में राष्ट्र किस मुकाम पर होगा। उन्होंने भारत के लिए एक विजन और दीर्घकालिक लक्ष्य तय किया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने व्यापक लक्ष्य को विभिन्न माध्यमों से दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों में विभाजित किया है और इसमें सरकार के हर वर्ग, पहलू और क्षेत्र को समावेश किया है। लक्ष्य चाहे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का हो या फिर व्यवसाय की सुगमता का या फिर वैश्विक निर्यात का प्रतिशत या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सा बढ़ाने का हो, इनके बारे में एक स्पष्ट रुख अख्तियार किया गया है और इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयास भी चल रहे हैं। आर्थिक और वित्तीय मानदंडों पर भारतीय अर्थव्यवस्था आज सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। इसकी विकास की दर आठ प्रतिशत के इर्दगिर्द घूम रही है। प्रधानमंत्री अपने प्रत्येक संबोधन में देश की हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय 140 करोड़ भारतीयों को देते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश और समाज के जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास की गति को बल न मिल रहा हो। कोरोना काल खंड हो या कश्मीर में 370 को हटाना या फिर यूक्रेन संकट या फिर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर हर जगह भारत की विदेश नीति की कुशल छाप दुनिया में देखी जा रही है।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी की तीन विशेषताएं हैं। एक, ये ईमानदार हैं। दूसरे, योग्य हैं, और तीसरे, मेहनती हैं। निश्चित रूप से उनकी वित्तीय ईमानदारी में आज तक किसी को शक नहीं रहा। उनके कट्टर से कट्टर विरोधी भी उनके व्यक्तिगत रूप से बेईमान होने का संदेह व्यक्त नहीं करते। जहां तक उनकी योग्यता एवं दूरदर्शिता का सवाल है, शायद वे अब तक जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं उनमें इस दृष्टि से सबसे ज्यादा दूरदर्शी हैं। उनके मेहनती होने के बारे में बताया जाता है कि वे 73 साल की उम्र होने के बावजूद, सोलह सोलह घंटे काम करते हैं। कह सकते हैं कि किसी देश को इससे बेहतर प्रधानमंत्री और क्या मिल सकता है, जिसमें ये तीन–तीन दुर्लभ गुण हों? कह सकते हैं कि मुश्किल से ही किसी मुल्क को मिलता है ऐसा प्रधानमंत्री। ऐसे योग्य, कर्मठ, वि. जनरी, ईमानदार प्रधानमंत्री ने आज देश की दशा और दिशा बदल कर रख दी है।

आर्थिक उदारीकरण से पहले श्रमिकों, कामगारों को जो अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं, उसमें काफी सुधार आया है। खेती–किसानी के लिए कमजोर रूप से किसान को 6000 रुपये की वित्तीय सब्सिडी मोदी सरकार द्वारा दी जा रही है। विदेशी पूंजी का निवेश हो रहा है। सेंसेक्स अभी तक के सबसे उच्चतम स्तर पर जा चुका है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक व खेलों की दुनिया में भी भारत का अद्भुत विकास हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज योग पूरी दुनिया में छा गया है और यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम रहा कि आज पूरा विश्व हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग दिवस की ही तरह विश्व अहिंसा दिवस को भी दुनिया ने स्वीकार कर शांतिपूर्ण एवं अहिंसक जीवनशैली को बल दिया है। आयात से अधिक निर्यात हो रहा है। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था का प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से संचालन कर पा रहे हैं। उसकी विशेषता रही है कि वैश्विक आर्थिक मंदी का उस तरह इस देश को सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह से आज पश्चिमी देश मंदी का सामना कर रहे हैं। एक बड़ा गुण निश्चित रूप से प्रधानमंत्री में होना चाहिए, वह है जनता से जुड़ाव। मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक जनता से संवाद कायम किया है और अब तक के सारे मिथक तोड़ दिये हैं।

–ललित गर्ग

यूपी के उपहास से दम तोड़ती यात्रा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1985 में आखिरी बार कांग्रेस सरकार बनी थी तब कांग्रेस ने 1980 और 1985 दोनों ही चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी उसके बाद से यूपी में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। यूपी एक ऐसा प्रदेश जिसने देश को पांच प्रधानमंत्री दिए जिनमें आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं उस प्रदेश में समाजवादी दल,बसपा और रालोद जैसे दलों ने भी सरकार चलाईं है। इनमें चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती रहीं हैं जिन्होंने बहुजन समाज को साथ लेकर और समाजवादी पार्टी ने पिछड़ावर्ग और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर कांग्रेस के ख़लिाफ़ जबरदस्त माहौल बनाया। सन् 1991में भाजपा के कल्याण सिंह सिर्फ डेढ़ माह मुख्यमंत्री रहे और गर्दा उड़ा दिए । मुलायम सिंह के शासनकाल में बावरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाता है और राममंदिर की लड़ाई ने यहां हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर दिया जिसके बाद से यहां धीरे–धीरे मज़बूत होती चली गई।यही वजह है कि उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ बन गया। एक घटना ने प्रदेश की फिज़ा बदल दी दलित,पिछड़ा और अल्पसंख्यक हताश और निराश तो हुआ किंतु दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हिंदुत्ववादी धारा में बह गए।

ऐसे हालात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मायनेखेज़ हो जाती है।इस बीच पिछले विधानसभा चुनाव में 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' के ज़रिए प्रियंका गांधी ने महिला अत्याचार के ख़लिाफ़ बिगुल तो फूंका पर वह अवसर वादिता थी । पीड़ित महिलाओं सहित जुझारू महिलाओं को टिकिट भी कांग्रेस ने दिए लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी।वजह वहीं थी बहुसंख्यक महिलाओं का हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण। लेकिन इस बार बिहार में तेजस्वी की तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के बीच पहुंचकर जिस सरकार को बदलने की पहल की जा रही है थी वह सरकार के अच्छे के कार्यों को नहीं झुठला सके ।इस राज्य में उपेक्षित दलित, पिछड़ावर्ग और अल्पसंख्यकों के बीच मोदी नाम की काफ़ी सरगर्मी है।यदि वे जाग गए तो 8 से 10 सीट इस गठबंधन को जीतना मुश्किल होगा। वहीं ये आशा भी बंधती है सोनिया गांधी और राहुल द्वारा अपनी सीट छोड़ने के बावजूद कांग्रेस और सपा मिलकर दस का आंकड़ा पार लेगी। यह विश्वास उत्तर प्रदेश में मोदी गढ़ वाराणसी मे राहुल के रैली से पु ख्ता हुआ। कतिपय सहयोगियों ने जब राहुल की न्याय यात्रा जो लगभग 12 किमी लंबी थी को ख़त्म होने के बाद उस रास्ते को गंगा जल से धोया ।इस कृत्य पर वाराणसी वासी शर्मसार नज़र नहीं आए।कई जगह जय श्री राम से इस यात्रा का स्वागत हुआ।कुछ असमाजिक तत्वों ने काला झंडा भी लगाया किंतु उसे राहुल आगमन से पूर्व हटा दिया गया। राहुल शाम भदौही ना जाकर वायनाड गए हैं जहां एक हाथी से कुचलकर मरे परिवार से साथ बड़ी सं ख्या में लोग आंदोलनरत हैं।बताया गया है सोमवार से 21फरवरी तक यह यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेंगी।

ये चंद रोज़ ही सही तानाशाह हुक्मरान के ख़लिाफ़ एक चुनावी बगावत का शं खनाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा भाजपा के गढ़ में कर रही है जिसमें वहां के युवा साथी पूर्व अखिलेश यादव अपने दल–बल के साथ पूर्ण रूप से सहभागी हैं।इस संग साथ का उत्तर प्रदेश में बहुत असर पड़ेगा। राजनैतिक दलों में हालांकि आया राम गया राम से इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी।जो सतत् चलते हुए अब चरम पर आ चुकी है। दमोह के पथरिया क्षेत्र में नगरपंचायत चुनाव में तो एक प्रत्याशी ने एक दिन में तीन दल बदलने का रिकार्ड कायम किया है।यह सब सत्ता प्राप्ति,सत्ता के साथ का सुख और सबसे बड़ा अपने अपराध से बचने के लिए होता है।अब सत्ता प्राप्ति की ललक कम हो गई है सत्ता के साथ रहने के सुख और अपने अपराधों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है।

इस बार के आमचुनाव से पहले ईडी, सीबीआई वगैरह ने जिस तरह छापामारी कर विपक्ष और उनके साथियों को आक्रांत किया है उसकी दबिश इतनी है इस तरह के तमाम लोग दहशतज़दा भाजपा वाशिंग मशीन की ओर मुताबिक होते जा रहे हैं जो उनके काले धब्बे साफ़ कर देती है।यह सरकार का आम चुनाव में नया प्रयोग है वह इसमें सफल भी नज़र आ रही है।पहले कहा जाता था कि जो बाप का नहीं हुआ वह किसी का कैसे हो सकता है किंतु अब बदलाव बड़े पैमाने पर हो रहा हो तब इन छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ़ कांग्रेस है जो अपने कुछ साथियों के साथ इसे अनीति और अन्याय मान इसके ख़लिाफ़ खड़ी है। नीतीश कुमार अनेकों मिल जाएंगे जनाब लेकिन हेमंत सोरेन होना शर्म की बात है।भाजपा के इस नए प्रयोग ने अच्छों अच्छों की पोल खोल दी है जो अब तक बड़े उदार और साफ़ दामन की बात करते रहते थे।सही कहा जाए तो इस प्रयोग ने लालची जमूरों को नानी याद दिला दी है। इन्हें भली–भांति जनता को जान पहचान लेना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस से अब तक जो गए हैं निश्चित तौर पर उनके दामन गंदे होंगे।आने वाले कल में इनके साथ क्या सुलूक होगा ये अंदर की बात है।आज के समय में हेमंत सोरेन होना शर्म की बात है।

पंकज कुमार मिश्रा,
जौनपुर यूपी

किसान संगठनों ने आम किसानों के दीर्घकालिक हितों लगाया दांव पर

दिल्ली चलो का आह्वान करने वाले लोग खुद को किसानों का नेता बताते हैं लेकिन सवाल उठता है कि यह आखिर कैसे नेता हैं जो किसानों का भला नहीं चाहते। सरकार ने वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों में एक बेहतर प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को तैयार करते समय सरकार ने पंजाब के किसानों की दिक्कतों का खासतौर पर ध्यान रखा लेकिन फिर भी उसे ठुकरा दिया गया। देखा जाये तो खुद को किसान नेता कहने वाले लोगों ने सरकारी एजेंसियों द्वारा पांच साल तक दाल, मक्का और कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर किसानों के हितों को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया है।

पहले जरा सरकार के प्रस्ताव पर नजर डालते हैं फिर आपको बताएंगे कि कैसे यह पंजाब के किसानों के हित में था। हम आपको बता दें कि किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जैसी सहकारी समितियां 'अरहर दाल', 'उड़द दाल', 'मसूर दाल' या मक्का का उत्पादन करने वाले किसानों के साथ एक अनुबंध करेंगी ताकि उनकी फसल को अगले पांच साल तक एमएसपी पर खरीदा जाए। उन्होंने कहा था कि खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि भारतीय कपास निगम उनके साथ कानूनी समझौता करने के बाद पांच साल तक किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा।

अब जरा समझिये यह प्रस्ताव किसानों के हित में कैसे था। दरअसल गेहूं और धान की फसलों में सर्वाधिक पानी लगता है। पंजाब उन राज्यों में शुमार होता जा रहा है जहां जल संकट धीरे–धीरे बढ़ रहा है। बड़े किसानों के पास तो फिर भी संसाधन हैं मगर एक छोटे किसान के लिए हाल के वर्षों में भूजल निकालने की लागत बढ़ गयी है इसलिए यदि यह किसान उन फसलों की ओर मुड़ते जिनमें पानी की अधिक खपत नहीं होती तो उनकी लागत कम हो जाती। सरकार चाहती है कि गेहूं और धान से अलग फसलें उगाकर किसान विविधता लायें। इसके लिए सरकार उनको पांच साल तक पूरी मदद की गारंटी भी दे रही थी। देखा जाये तो सरकार का यह प्रस्ताव पंजाब के लिए आदर्श था, जहां भूजल स्तर चिंताजनक रूप से कम हो गया है।

आंकड़ों के जरिये समझायें तो आपको बता दें कि इस समय पंजाब के अधिकांश क्षेत्र में गेहूं और धान की खेती (2020–21 में 85प्रतिशत) होती है। पंजाब में कपास, दालों और मक्का के लिए पारिस्थितिकी तंत्र (बाजार, खरीदार, रसद, इनपुट आपूर्ति, आदि) उतना सशक्त नहीं है इसलिए सरकार किसानों को अपने समर्थन की गारंटी देना चाह रही है। अभी के संदर्भ में देखें तो मक्का 1.5प्रतिशत, कपास 3.2प्रतिशत और दालों की केवल 0.4प्रतिशत खेती हो रही है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किसान यदि इन फसलों की ओर बढ़ते हैं तो नये बाजार खुलेंगे। साथ ही किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए निजी क्षेत्र में भी बड़े खरीददार मिलेंगे।

देखा जाये तो केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार करके, किसान संगठनों ने अपने अल्पकालिक हितों के लिए पंजाब के आम किसानों के दीर्घकालिक हितों को दांव पर लगा दिया है। गेहूं और धान से दूर जाने की अनुमति नहीं देकर ये यूनियनें न केवल किसानों को नए बाजार तलाशने से रोक रही हैं, बल्कि भूजल तनाव भी बढ़ा रही हैं। इस सबसे यकीनन किसानों के लिए इनपुट लागत बढ़ जाएगी। जहां तक बात इन कृषि यूनियनों की है तो हमको यह भी समझना होगा कि इनमें ज्यादातर मंडियों में काम करने वाले दलाल और आढ़ती शामिल हैं। यह लोग सिर्फ अपने भारी कमीशन को प्राथमिकता दे रहे हैं ना कि किसानों के हितों को। हम आपको बता दें कि एपीएमसी मंडियों में गेहूं और धान के व्यापार से दलाल और आढ़ती बड़ी रकम कमाते हैं। बहरहाल, कुल मिलाकर देखा जाये तो यह आंदोलन पंजाब के किसानों के हितों के लिए नहीं बल्कि बिचौलियों के कमीशन को सुरक्षित रखने के लिए चलाया जा रहा है।

नीरज कुमार दुबे

विपक्षी एकता कायम रही तो भाजपा को हराना कोई बड़ी बात नहीं

इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस का दायित्व बनता है कि वह गठबंधन में शामिल सभी दलों को साथ लेकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बं. टवारे जल्दी से करे। मगर अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है।

केंद्र में सत्तारुढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए देश के 28 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन बनने से देश के लोगों को राजनीति में एक नया विकल्प तो मिला ही है। उसके साथ ही उन्हें लगने लगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देंगे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सहित कई राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इनमें से बहुत–सी क्षेत्रीय पार्टियों की उनके प्रदेशों में सरकार भी चल रही है। इंडिया गठबंधन की कई बैठकें भी हो चुकी हैं। मगर गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने से आपसी मनमुटाव की स्थिति बनी हुयी है।

इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस का दायित्व बनता है कि वह गठबंधन में शामिल सभी दलों को साथ लेकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारे जल्दी से करे। मगर अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। चूंकि देश में 10 साल बाद भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है। इसलिए इसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए इसका संयोजक भी बनाया जाना चाहिए था। मगर कई महीने निकल जाने के बाद भी अभी तक विधिवत रूप से इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम घोषित नहीं हो पाया है। सीटों का बंटवारा नहीं होने के कारण गठबंधन में शामिल कई राजनीतिक दल नाराजगी जाहिर करने लगे हैं।

इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस द्वारा बरती जा रही ढलाई के चलते ही बिहार में जनता दल यू गठबंधन से बाहर होकर फिर से एनडीए में शामिल हो गया है। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार भी बना ली है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को बनाने वाले मुख्य राजनेताओं में शामिल थे। वह इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे। मगर गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं में आपसी खींचातान के चलते नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन सके। इसी से खफा होकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। जीतन राम मांझी की हम पार्टी बिहार में पहले ही इंडिया गठबंधन से बाहर निकल चुकी थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी भाजपा से गठबंधन कर इंडिया गठबंधन को अलविदा कह दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष व मु ख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी दलों से किसी भी तरह का चुनावी गठबंधन करने से इंकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के लिए उनकी मौजूदा दो लोकसभा सीटों को ही छोड़ने की बात कही है। जबकि कांग्रेस वहां अधिक सीटों पर दावा कर रही थी। इससे वहां सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी त्रिपुरा, असम और गोवा में भी चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अ खिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा नहीं होने के चलत 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की एकतरफा घोषणा कर दी थी। इनमें वह लोकसभा सीटें भी शामिल हैं जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अखिलेश यादव की एकतरफा घोषणा से उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। मगर कांग्रेस ने अखिलेश यादव की सभी शर्तें मान कर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को टूटने से बचा लिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं।

बिहार में राजद, कांग्रेस, वामपंथी दलों को मिलकर चुनाव लड़ना है। मगर वहां नीतीश कुमार की जदयू के गठबंधन से बाहर जाने के बाद लालू प्रसाद यादव की राजद 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। जबकि कांग्रेस वहां 10 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वामपंथी दल भी वहां आठ सीटों पर दावा कर रहे हैं। ऐसे में यदि समय रहते बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो गठबंधन की गांठ ढ़ीली पड़ जाएगी।

तमिलनाडु में कांग्रेस ने 2019 में द्रुमक के साथ मिलकर नौ सीटों पर चुनाव लड़कर आठ सीट जीती थी। मगर अब कांग्रेस वहां 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जबकि द्रुमक कांग्रेस को 7 सीट ही देना चाहती है। तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में सीट बंटवारे को लेकर आपसी रार मची हुई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में तीन सीट देने की बात कही है। वहीं पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक बात नही बनी है। पंजाब के मु ख्यमंत्री भगवंत मान ने तो पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी थी। आप ने कांग्रेस से हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम की कुछ सीटों की भी मांग की है।

महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) व कांग्रेस की महाविकास अघाडी के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के प्रकाश अंबेडकर के शामिल होने से महाविकास अघाड़ी मजबूत हुई है। मगर महाराष्ट्र में भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एकजुटता के साथ चुनाव में उतरने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा तभी वह भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन के संयोजक का चयन करना होगा।

गठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां उनके लिये अधिक सीटें छोड़े ताकि वह भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकें। वहीं कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे प्रदेश जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां वह अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, त्रिपुरा, गोवा जैसे राज्यों में बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गई है। इन प्रदेशों में क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं। ऐसे में कांग्रेस को इन प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए ताकि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एक साथ मिलकर भाजपा नीत एनडीए से मुकाबला कर सकें। कांग्रेस के नेता जब तक बड़ा मन रखकर सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं देंगे तब तक गठबंधन में शामिल नेताओं में आपसी मनमुटाव जारी रहेगा। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को सबसे पहले सीटों का बंटवारा कर मनमुटाव की स्थिति को समाप्त करना होगा। तभी इंडिया गठबंधन एकजुट से चुनावी मुकाबले में उतर पायेगा।

रमेश सर्राफ धमोरा

सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए बदलाव की डगर पर यूएई

युएई के नए कानून के तहत गैर–मुसलमानों को अबू धाबी में नागरिक कानून के तहत विवाह–तलाक और संयुक्त बाल हिरासत प्राप्त करने की अनुमति दी जायगी अर्थात अब धाबी में रहने वाले गैर–मस्लिमों अपने तरीके से शादी कर सकेंगे, तलाक ले सकेगे और बच्च्वों की कस्टडी अपने हिसाब से प्राप्त कर सकेंगे। शरिया का कोई दखल नहीं होगा।

खाडी देशों के पास राजस्व का एकमात्र स्त्रोत प्राकृतिक तेलों के भंडार हैं। आने वाले दशकों में ये भंडार समाप्त हो जाएंगे इससे पहले इस्लामिक देश मजबूत आर्थिक आधार खड़ा करना चाहते हैं। इस्लामी कानून इसमें आड़े आ रहे थे। ऐसे में इन देशों ने शरीया कानूनों में ढील देना शुरू कर दिया है। पर्यटन और औद्यागिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खाड़ी देश अपनी नीतियों में लगातार बदलाव कर रहे हैं। यूएई में मंदिर बनना इस बदलाव का ऐतिहासिक उदाहरण है। खाड़ी देशों के लिए दूसरे देशों में मसलम. ानों के साथ क्या हो रहा है, इससे अब ज्यादा सरोकार नहीं है। इन देशों की प्राथमिकता अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ करना है। यही वजह रही कि चाहे चीन के युआन प्रांत में मस्जिदों के ढहाने के मामले हों या इसराइल–फिलिस्तीन युद्ध में फिलिस्तिनियों के जाने का मुद्द हो, खाड़ी के मुस्लिम देशों ने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। यहां तक कि चीन के खिलाफ कभी एक लाइन का बयान तक जारी नहीं किया गया। चीन के दीगर मुसलमानों के दमन की खबरें बाहर आती रही हैं और उनको जबरन निगरानी कैम्पों में भी भेजा जाता रहा है।

चीन इन कैम्पोंको रिएजुकेशन कैंप बताता है। इन सभी मामलों में दुनिया के मानवाधिकार संघटनों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश खुलकर चीन को निन्दा कर चुके हैं और करते रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम देशोंकी ओर से इस पर कोई नहीं आया। मुस्लिम देशों के संघटन ऑर्गनाइजशन आफ इस्लामिक कार्पोरेशन (ओआईसी) ने भी इस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। यहां तक कि बीते वर्ष मार्च में पाकिस्तान में हुई ओआईसी की बैठक में चीन के तत्कालीन व देश, मंत्री वांगयी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। ओआईसीकी बैठकके दौरान वांग यीने वादा किया था कि बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) के तहत चीन मुस्लिम देशों में 400 अरब डालर निवेश करेगा। लोकतांत्रिक देश चीन में मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओआईसी के सदस्य देश पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्त्र और कुवैत चीनकी तारीफ करते रहे हैं। दुनिया की कुल आबादीमें से इस्लाम माननेव. ालोंकी आबादी दो अरब है। इसमेंसे 85 फीसदी शिया और 15 फीसदी सूत्री मुसलमान हैं। इस्लाम कोई 1400 वर्ष पुराना धर्म है। इसमें मूर्ति पूजाकी मनाही है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान है। इसी के आधार पर कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन समयके साथ इस्लामको मानने वाले बदल भी रहे हैं। सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सऊदीकी अर्थव्यवस्था तेलपर निर्भर है। सऊदी 2030 तक अपनी इस अर्थव्यवस्था को बदलना चाहता है और पर्यटनपर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। दुनिया में जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आनेवाले दिनों में

तरल ईधनपर निर्भरता कम होगी, ऐसे में आय के दूसरे स्रोत खड़े करने के लिए उदारता बरतना आवश्यक हो गया है। इसीलिए इस्लामिक देशों में कट्टरता से मुक्ति के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। पर्यटन और दूसरे क्षेत्रों में निवेश को आमंत्रित करने के लिए बदलाव की

शुरुआत अऊदी अरब से हुई है। प्रमुख इस्लामिक देश सऊदी अरब ने अपने देश में कटतास मुक्ति की ओर बढ़ते हुए अपने देश में विदेशियों के लिए शराब की दकान खोलने की इजाजत दी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने देश की राजधानी रियाद में यह मंजूरी दीं।

यहां पिछले दिनों महिलाओ को कार चलाने, पुरुषों के साथ कार्यक्रमो में शामिल होने सिनेमाघरों में जाने और संगीत के कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट भी दी गई है। इस्लाम में पहले महिलाओं को यह आजादी नहीं थी। प्राकृतिक तेल स्त्रोत विकल्प के तौरपर सऊदी अरब अब पेरिस और लंदन की तराह पर्यटकों को आक्र्षित करनेके लिए राजधानी रियाद में दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक शहर को विकसित कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के परे होने की उम्मीद 2030 तक जताई जा रही है। वहीं, इस प्रोजेक्टकी कुल लागत गैर–तेल जीडीपी के लिए 160 बिलियन सऊदी रियाल अथात् 48 .6 बिलियन डालर आनेकी उम्मीद है। इस परियोजनाके अंतर्गत 19 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर किया जायगा और इसमें एक संग्रहालय, एक प्रौद्योगिकी, डिजाइन विश्वविद्यालय, एक बहु–उद्देश्यीय थिएटर और 80 से अधिक मनोरेंजन और संस्कृति स्थल होंगे। इस्लामिक देश अब कबीलाई कानूनोंको छोड़कर अर्थव्यवस्था मजबूत करनेकी तरफ कैसे बदलाव कर रहे हैं, इसका उदाहरण कतर भी है। भारत ने कतर से कथित जासूसी के आरोप में अपने पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाया है। नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को कतरने पहले फांसी की सजा सुनाई थी।

भारत की पहल पर इनकी फांसी की सजा को कारावास में तब्दील कर दिया गया । इसके बाद इनकी यह सजा भी माफ कर दी गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अबुधाबी में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कतर के दौरे पर गए। मोदी का वहां भव्य राजकीय सम्मान किया। कतर में यह बदलाव सोची–समझी रणनीति के तहत अया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है भारत ने कतर को बहत बड़ा कॉन्ट्रेक्ट दिया है। 2048 भारत कतर से गैस आयात करेगा। इसकी वैल्य 78 बिलियन डालर है। यही वजह रही है कि कतर ने न सिर्फ पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया, बल्कि पीएम मोदीका शानदार स्वागत भी किया। भारत को इस करार से फायदा यह है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्बाधित गैस मिलती रहेगी। सऊदी अरब की तरह यूएई भी इस्लामी कानूनों को पीछे छोड़ बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूएई में हिन्दू मंदिर का निर्माण है युएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिन्दू मंदिर स्थापित किया गया है। लगभग 27 एकड़ में फैले स्वामीनारायण मंदिर परिसर के लिए यूएई सरकार ने इसके लिए जमीन दान की। समझा जा रहा है कि इतने भव्य हिन्दू धर्मस्थल का बनना यूएई और भारत के रिश्तों को और मजबूत करेगा । युएई बाकी इस्लामिक देशों से अलग रहा है। यहांतक कि मध्यपूर्व में राजनीतिक गुट माने जाते कई संघटनों को उसने अपने यहां बैन कर दिया, ताकि देश कट्टता से बचा रहे, लेकिन पूर्व में यूएई में इस्लामी कट्टरता बनी रही।

यूएई की कट्टरता की एक झलक इस बात से दिखती है कि वहां अल्पसंख्यक जमीन का मालिकाना हक नहीं पा सकते, विशेषकर धार्मिक कामों के लिए यही वजह है कि अमीरात में ताकतवर पदों और आबादी के बाद भी अल्पसंख्यक अपनी मर्जी से धार्मिक स्थल नहीं बना सकते। वे ऐसा तभी कर सकते हैं, जब सरकार जमीन डोनेट करे या लीज पर दे। हिन्दू मंदिर के लिए जमीन देकर यूएई ने अपना उदारवादी चेहरा पेश किया है, ताकि भविष्य की जरूरतों के लिहाज से विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। इससे पूर्व यूएई सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए कई बंदलाव कर चुका है।

युएई के नए कानून के तहत गैर–मुसलमानों को अबू धाबी में नागरिक कानून के तहत विवाह–तलाक और संयुक्त बाल हिरासत प्राप्त करने की अनुमति दी जायगी अर्थात अब धाबी में रहने वाले गैर–मस्लिमों अपने तरीके से शादी कर सकेंगे, तलाक ले सकेगे और बच्च्वों की कस्टडी अपने हिसाब से प्राप्त कर सकेंगे। शरिया का कोई दखल नहीं होगा।

वसन्ती कुण्डलिया

मौसम मदमाने लगा,शोभन लगे वसंत।
मधुमासी परिवेश ने,किया विरह का अंत।।
किया विरह का अंत,आज तो चंचल मन है।
खुद से ही है दूर,आज खुद का ही तन है।।
अमराई में कूक,फुर्र तो है अब सब ग़म।
खिलने लगा पलाश,बहुत ही भाता मौसम।।

(2)

बहकी शीतल वायु है,शोभन लगे वसंत।
प्रेमिल अब मौसम हुआ,तोड़ रहे तप संत।।
तोड़ रहे तप संत,मिलन की ही सब बातें।
दिन में प्रिय की याद,लग रहीं सूनी रातें।।
लगे गुलाबी ठंड,ताप से काया दहकी।
हर कोई मदमस्त,सभी की गति है बहकी।।

(3)

पलता हैआनंद अब,शोभन लगे वसंत।
ढूंढ रहीं अंखियाँ व्यथित,कहाँ गए हैं कंत।।
कहां गए हैं कंत,मिलन हो जाए चोखा।
जाने कोई हाल,खा गया यह दिल धोखा।।
है वियोग की मार,वसंती मौसम खलता।
व्याकुल है अनुराग,हृदय में प्रियवर पलता।।

(4)

बहक रही है सृष्टि अब,हुआ सुवासित प्यार।
नेहिलता से भर गया,आज सकल संसार।।
आज सकल संसार,वसंती दौर आ गया।
अमराई खुशहाल,पेड़ पर बौर आ गया।।
झूमें हम मनमीत,चेतना महक रही है।
अधरों पर नवगीत,नज़र अब बहक रही है।।

(5)

आशा गाती गीत अब,है वसंत का नेह।
आतपमय होने लगी,देखो तो अब देह।।
देखो तो अब देह,फूल हैं हर उपवन में।।
जागा है अब काम,संत के भी तो मन में।।
हर दिल में अभिसार,सभी ने तजी हताशा।
दूर हुआ नैराश्य,चरम पर सब की आशा।।

प्रो(डॉ)शरद नारायण खरे
मंडला मप्र

आजीवन कृष्ण भक्ति में डूबी रही जेबुन्निसा

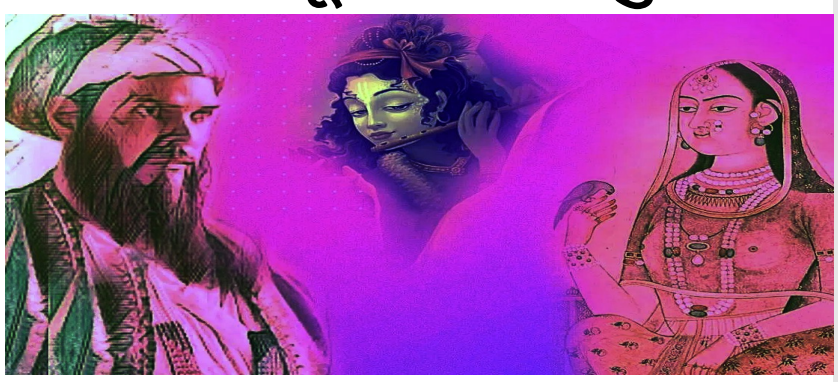

औरंगजेब का नाम मुगलों के सबसे कट्टर शासकों में आता है। कहा जाता है कि मुगलों के दौर का या आखिरी बादशाह था, जिसमें मुगल मजबूत रहे। इसके बाद से मुगलों का पतन शुरू हो गथा था हालांकि, औरंगजेब अब तक रहा उसने मजहबी कट्टरता को सबसे ऊपर रखा। स्थिति ये थी कि इस कट्टरता से उसकी खुद की बेटी भी नहीं बच पाई जो जिंदगी भर कृष्ण भक्ति में जबी रही और इसके लिए पिता से ताउम सजा पाती रहीं। जेबुन्निसा, औरगजेब और बेग दिलरस बानो की सबसे बडी बेटी थीं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये वचपन से ही होनहार थी, इनका बचपन शुरू से ही सबसे ज्यादा पढाई लिखाई में लगता था। यहीं वजह है कि इन्होंने दर्शन, भूगोल, इतिहास जैसे विषयों को पढ़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि, औरंगजेब ने इनकी मंगनी चचेरे भाई सुलेमान शिकोह से कर दी थी लेकिन सुलेमान शिकोह की कम उम्र में ही मौत हो गई। इसके बाद जेबुन्निसा ने अपना पूरा ध्यान पढाई लिखाई और शायरियों में लगा दिया। औरंगजेब को अपनी बेटी से प्रेम था, लेकिन उसको ये पसंद नहीं था कि उसकी बेटी शायरियाँ करे और मुशायरों में जिए। कहा जाता है कि एक दिन औरंगजेंब को "भनक लगी कि उसकी बेटी किसी हिंदू बंदेला राजा के साथ प्रेम में है, तो वह आगबबूला हो गया। इसके बाद अपनी बेटी को कैद करवा लिया। वो इस कैद में लगभग 20 साल रही है कि कैद में रहते हुए वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने अनेक रचनाएँ लिखी। बाद में 'दीवान–ए–मखफी' नाम से इन्हें प्रकाशित भी किया गया हालांकि 1702 में जेबुन्निसा की मौत हो गई।

डर जाना नहीं

तन सुंदर और मन सुंदर
सुन्दर यह संसार है
जीवन भी हो जाये सुन्दर
अगर मानवता से प्यार है
सुन्दर बनना है तो,
मन को सुन्दर बना लो
जीवन का पल पल
अब तो सुन्दर बना लो
सुंदरता तो वक्त के,
साथ ढल जाती है
अहंकार मानवता को,
छल जाती है
अगर जीवन बन गया,
तेरा सुंदर तो
बदलाव आ जाये अब,
मन अंदर तो
जिंदगी ख्वाब से,
हकीकत में बदल जायेगी
हर बार फिर से बहारे,
नया परिवर्तन लायेगी
परिवर्तन से कभी भी,
घबराना नहीं
होगा बदलाव अब तो,
डर जाना नहीं

प्रमेशदीप मानिकपुरी
आमाचानी धमतरी छग

जीवन के दिन

कितने हैं किसी के जीवन के दिन
यह जीवन मिला है सबको उधार
न किसी को पता है न कोई है जानता
कोई चुका देगा कोई नहीं पाएगा उतार
चार दिन की ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाएगी
पाप की यह गठरी भरती ही जाएगी
हिसाब तेरे कर्मो का है रखा जा रहा
छुपा न पायेगा कुछ भी हकीकत सामने आएगी
फुर्सत में सोचना अकेले में बैठकर ज़रा
पैसे से भी भला किसी का कभी पेट है भरा
करता रहा उम्र भर इक्ठी पाप की दौलत
दिखावा दिलेरी का मगर अंदर से रहता है डरा
लॉकर तेरी दौलत के सब रह जाएंगे बन्द पड़े
मौत जब आएगी तब पहरेदार सो जाएंगे खड़े खड़े
कितना ज़ोर लगा ले कोई बच नहीं पायेगा
जब भर जाएंगे तब टूट जाएंगे तेरे पाप के घड़े

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

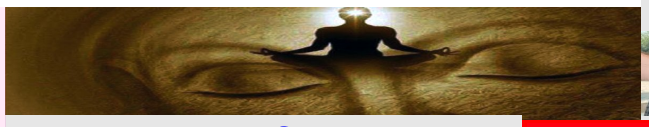

आत्म चिंतन

जब कुछ पुराने सम्मानित सहयोगी, सलाहकार, हितेशी, चाहने वालों... से काफी समय से संपर्क नहीं होता है, न फोन, पत्र, व्यक्तिगत किसी भी माध्यम से । तो इसका मतलब ये कतई न निकालें कि सामने वाला उन्हें भूल चुका है। यादें जिंदा रहती हैं, बस वे सो जाती हैं या यूं कहें कि कुछ धूमिल हो जाती हैं ।

इंसान जब पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक संघर्षों से जूझता है तब वह अपने सच्चे चाहने वालों से धीमें–धीमें दूर होता चला जाता है। और सच्चे हितैषी उसे स्वार्थी समझ बैठते हैं। बस यहीं से आपसी संबंध टूटते चले जाते हैं। कुल मिलाकर गलती दोनों तरफ से होती है। तो क्यों न इस गलती को समय रहते पुनः सुधारा जाये। आइए मिलाइए हृदय से हृदय...

मुकेश कुमार ऋषि वर्मा
फतेहाबाद, आगरा

प्रिय पाठकों,

इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, कथा–लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की विशेषता होती है।

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट भी समय–समय पर कराते रहें ताकि उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

विवाद की स्थिति में न्यायालय, गोरखपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

–व्यवस्थापक

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक–पंकज धर द्विवेदी सम्पर्क सूत्र– e-mail- ghoonghatkibagawat37@gmail.com